RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 271
दि. 02.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम महान संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का उद्घाटन किया

जालंधर , (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब के जालंधर पहुंचे। वह यहां धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक हुए। डेरा सच्चखंड बल्लां, जो गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा का प्रमुख और प्रभावशाली केंद्र है। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आदमपुर एयरपोर्ट का नाम महान संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का उद्घाटन किया। इस मौके पर डेरा सचखंड बल्लां सहित विभिन्न स्थानों से पहुंची संगत और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के नए नाम का औपचारिक एलान किया, पूरा परिसर रविदास शक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं पंजाब की इस मिट्टी को नमन करता हूं। आज गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। मुझे इस पुण्य अवसर पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। काशी के घाटों पर ही संत रविदास जी की शिक्षा प्रकट हुई थी। हम सभी उनसे बहुत प्रेरणा पाते हैं।

उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता गुरु रविदास जी की जन्म भूमि काशी से है। मुझे वहां से आशीर्वाद मिला है। काशी करोड़ों लोगों की तीर्थ भूमि है। मैं श्री गोवर्धन जाता हूं तो पंजाब के काफी लोग मिलते हैं। मैं इस बार पंजाब आया हूं यह गुरु रविदासकी इच्छा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे निमंत्रण के लिए डेरा अभिनंदन है।

ईयू के साथ हुए एफटीए से पंजाब को होगा लाभः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने आज पेश किए गए यूनियन बजट पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले 11 साल में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई हैं। गरीबों और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई हैं। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैंसर के इलाज को और सस्ता करने के लिए अनेक कैंसर दवाओं को और सस्ता किया गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से पंजाब सहित भारतीय निमार्ताओं को अपने उत्पादों के निर्यात में लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का जीवन समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने विचारों से समाज

को नई दिशा दी और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखना, उनकी शिक्षाओं के प्रति सम्मान और आने वाली पीढ़ियों को उनके विचारों से जोड़ने का प्रयास है।

इस अवसर पर पंजाब के सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, संत समाज, संगत और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। संगत ने गुरु रविदास जी की तस्वीरों और झंडों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और सामाजिक सम्मान का संगम साफ नजर आया।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर किया जाना पंजाब की दलित राजनीति और सामाजिक चेतना के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। इसे राज्य में सामाजिक संतुलन और सम्मान की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

सुबह से ही डेरा परिसर में रौनक बढ़ने लगी और दूर-दराज से पहुंची संगत प्रधानमंत्री के स्वागत और देखने को लेकर बेसब्री से इंतजार करती नजर आई। डेरा प्रबंधन और संगत की ओर से पूरे परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं और संदेशों से जुड़े बैनर-पोस्टर लगाए गए, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े और चाक-चौबंद इंतजाम किए गए।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सामाजिक समरसता और दलित चेतना से जुड़े बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। डेरा सच्चखंड बल्लां, जो गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा का प्रमुख और प्रभावशाली केंद्र है, वहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी को संगत ने सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में लिया। जय गुरु रविदास के उद्घोष के साथ संगत डेरा परिसर में जुटती रही और पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखाई दिया।

वहीं लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। हलवारा एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वाटर प्रूफ टेंट में विशाल मंच सज चूका है और मेहमानों का आना निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरपोर्ट से 3.45 पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा का वर्च्युअल उद्घाटन करेंगे।

सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता

प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। पंजाब पुलिस और एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के जवान डेरा बल्लां में तैनात हैं। डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां वे इस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा करेंगे। इसके अलावा वे लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी

लखनऊ को मिलेगा एआई सिटी का दर्जा:मेट्रो फेज-2 के लिए शहर को मिली धनराशि, बजट में राजधानी को प्रायोरिटी

लखनऊ (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट के बाद कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं ने खासतौर पर राजधानी लखनऊ को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। अक सिटी, मेट्रो विस्तार, हाई-स्पीड रेल और औद्योगिक निवेश से लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है।

केंद्रीय बजट में लखनऊ में अकसिटी विकसित करने के लिए विशेष बजटीय सहायता का ऐलान किया गया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और नई तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ मेट्रो के फेज-2 के लिए शहर को धनराशि भी मिल गई। बजट में राजधानी को प्रायोरिटी मिली है।

मेट्रो के अगले चरण को रफ्तार

लखनऊ मेट्रो के अगले चरणों के लिए केंद्र सरकार ने कानपुर और आगरा के साथ कुल ₹32,075 करोड़ का आवंटन किया है। इससे राजधानी में नए रूट्स पर मेट्रो विस्तार होगा और ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। शहरी परिवहन को मजबूत करने में यह बजट अहम साबित होगा।

दिल्लीझ्रवाराणसी और मुंबईझ्र

वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए बजट मंजूर किया गया है। जानकारों का मानना है कि भविष्य में इन कॉरिडोरों का सीधा या परोक्ष जुड़ाव लखनऊ से होने पर राजधानी की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को फायदा मिलेगा।

औद्योगिक गलियारों और एक्सप्रेसवे से बढ़ेगा निवेश गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए ₹22,500 करोड़ के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा असर लखनऊ और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। इससे राज्य को अधिक संसाधन मिलेंगे, जिनका बड़ा हिस्सा राजधानी लखनऊ के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास में खर्च होने की उम्मीद है।

लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से नई मजबूती वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब और प्रयागराज में औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड की घोषणा से पूरे प्रदेश की सप्लाई चेन मजबूत होगी। लखनऊ, जो प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र है, इस नेटवर्क का प्रमुख लाभार्थी बनेगा।

बजट घोषणाओं से साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में लखनऊ का सर्वांगीण विकास है। अक सिटी, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक निवेश के जरिए राजधानी को आधुनिक, स्मार्ट और रोजगारपरक शहर बनाने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर माना जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

पीएम ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा- हर घर लक्ष्मी जी पधारे यही कोशिश, क्यों अहम है संदेश?

केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "विकसित भारत की यात्रा को तेज करने वाला बजट" बताया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं और बीते सालों में सरकार ने लोगों की क्षमता बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है।

बजट 2026 में कृषि, महिला सशक्तिकरण, MSME, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि सरकार की कोशिश है कि "हर घर में लक्ष्मी जी पधारें", यानी हर परिवार की आय बढ़े और आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो।पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन (फिशरीज) हमेशा से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

'यूसीजी' को गाली देने वाले सभी ज्ञानी, मोदी जी पर भरोसा रखिए', भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया दावा

(जीएनएस)।

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी वक्रझ्र द्वारा जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद जहां एक ओर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है।

निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों पर निशाना साधा जो बीते दिनों से वक्रझ्र और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "वक्रझ्र पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान के दायरे में ही देश चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो पहले से कहा जा रहा था।" इसके साथ निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली खबर को रि-पोस्ट किया है।

"यूसीजी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी,पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूँ,किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इसपर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा? उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एहर को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीब की सुध ली,उसी को गाली । मैं दुबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मोदी जी पर भरोसा रखिए, संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे ।

सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा।"

भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा।" 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 'UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशंस 2026' के कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता नजर आती है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट का साफ कहना है कि किसी भी नियम का मकसद भेदभाव खत्म करना होना चाहिए, लेकिन अगर वही नियम नए टकराव और भ्रम को जन्म दें, तो उस पर दोबारा विचार जरूरी हो जाता है।

निशिकांत दुबे का तीखा बयान क्यों बना चर्चा का केंद्र

सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद इखढ सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच से जो बयान दिया, उसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह पिछले दो दिनों से संसद जा रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य ने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एहर को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीब वर्ग की चिंता की, उसी सरकार को गाली दी जा रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया है, जिसकी उम्मीद थी।

भाजना ने कोर्ट के फैसले को बताया संविधान और सनातन मूल्यों की जीत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इसे संविधान, सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों की रक्षा से जोड़कर देखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे, जिन्होंने एहर को आरक्षण दिया और गरीबों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। उनके मुताबिक कोर्ट का यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संतुलन को मजबूत करता है।

यूपी से बिहार तक बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सम्मान के योग्य होता है। उन्होंने राम मंदिर के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत के निर्णयों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, सरकार आदेश का पालन करेगी।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी।

भारत की राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान के उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (1 फरवरी, 2026)

अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया।

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे) उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं।

रोहिणी आचार्य बोलीं- 'पुराने सामान को नए डब्बे में परोसा गया

(जीएनएस)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को आम बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुईं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दिखी। जिसके चलते बजट को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। जहां एक ओर मोदी सरकार के बजट की बीजेपी नेता तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने आम बजट को जनता विरोधी करार दिया है। जानिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी?

केंद्रीय बजट 2026-27 पर उनकी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, लोकसभा के नेता राहुल गांधी कहते हैं, "मैं संसद द्वारा प्रदान किए गए मंच का उपयोग करके कल बोलूंगा।" वहीं कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, "मोदी के फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा है।"

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार के संघीय बजट पर तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस बजट की तुलना "पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने" से की है। रोहिणी आचार्य ने लिखा, "अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी कैसे होगी? इस पर बजट में कोई स्पष्टता नहीं है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात की गई है, मगर देश की शिक्षित व गैर-शिक्षित युवा आबादी के लिए यथार्थ में जॉब-क्रिएशन कैसे और किन-किन सेक्टर्स में होगा? देश के इस सबसे गंभीर मसले पर भी बजट में कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है।"

आचार्य ने बिहार से संबंधित एक पुरानी और अति आवश्यक मांग को लेकर भी निराशा जताई। उन्होंने कहा, "बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोक थाम, बाढ़ के पश्चात पुनर्वास की व्यवस्था एवं सिंचाई के संसाधनों के निर्माण व विकास के लिए विशेष-पैकेज दिए जाने की बेहद जरूरी व पुरानी मांग के लिए बजटीय प्रावधान का नहीं होना निराशाजनक है।"

कोरा बकवास बजट, झारखंड को कुछ नहीं मिला', भड़का झारखंड मुक्ति मोर्चा

(जीएनएस)।

झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें राज्य की उपेक्षा की गई है, जबकि बीजेपी की राज्य इकाई ने इसे 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिन में संसद में 2026-27 वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (खटट) के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि बजट में राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। पांडे ने आरोप लगाया, 'झारखंड के खनिज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी राज्य की उपेक्षा की गई है।'

'बीजेपी शासित राज्यों पर ही ध्यान'

बजट में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर ध्यान दिया गया है, जो सही नहीं है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा, "बजट में आम आदमी के लिए

कुछ नहीं है। इसमें रोजगार के बारे में कोई बात नहीं की गई है और महंगाई कम करने का कोई जिक्र नहीं है।'

'रेयर अर्थ कॉरिडोर में कोई जगह नहीं मिली'

उन्होंने कहा कि '40 प्रतिशत से अधिक खनिज भंडार वाले राज्य को केंद्रीय बजट में घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर में कोई जगह नहीं मिली। झारखंड बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय बजट की सराहना की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। यह भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट खाका पेश करता है। यह बजट गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जरूरतों को केंद्र में रखता है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए, यह नए अवसर और स्रोत बनाने की घोषणा करता है ताकि देश आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।'

इझ्रीइ 2026: 'यह बजट विकसित भारत बनाने के लिए है'

झारखंड बीजेपी प्रमुख आदित्य साहू ने इसे समावेशी, विकासोन्मुखी और रोजगार-केंद्रित बजट बताया। उन्होंने कहा, 'यह बजट रेलवे, सड़कों, स्वास्थ्य और छोटे और कुटीर उद्योगों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।" विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'यह बजट विकसित भारत बनाने के लिए है। यह महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने में मदद करेगा। यह रोजगार सृजन पर बहुत जोर देता है।'

सम्पादकीय

यूजीसी 2026 का विरोध क्यों?

यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थान में एससी-एसटी के साथ-साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया है क्योंकि यूजीसी का मानना है कि अब तक के पिछले प्रावधान वैंपस में जांच के भेदभाव को कम करने में या रोकने में नाकाम रहे हैं। यूजीसी अधिसूचना 2026 का विरोध क्यों? अभी हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मैं देश भर में उच्च शिक्षा संस्थान में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अनुसूचित किए हैं, इन नियमों के तहत प्रत्येक संस्थान के परिसर ने समानता इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है, इनका न पालन करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने और दंड का सामना पड़ सकता है। नए नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर वेंद्र स्थापित करना और समावेशन सुनिति करना है, इसके अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी गठित होनी है जिसका जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। कमेटी में ओबीसी विकलांग एससी-एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इक्विटी कमेटी को वर्ष में काम से कम दो बैठक करना अनिवार्य होग, प्रत्येक संस्थान को ईओसी के कार्य प्रणाली पर वरषिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न क्या उठना है कि इस नईं नियमावली की आवश्यकता क्यों पड़ी संभवतः इसके निम्न कारण दिखाईं देते हैंविश्वविद्याल य अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में क्षमता को बढ़ावा देना वन में 2026 को 13 जनवरी 2026 को अनुचित किया यह वर्ष 2012 से लागू भेदभाव रूपी नियमों का अध्यतन रूप है। पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित व भेदभाव के दायरे से बाहर रखा क्या गया था। मसौदा न्यू मूवी यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झुठी शिकायतों को हाथों उत्साहित करने के लिए जुमार्ने का प्रावधान किया जाए। अंतिम अधिवेशन नियमों में यूजीसी में ओबीसी को जाकर भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा परिभाषित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के भिन्नमालयों की निहित भाषा को भी शामिल किया जा सके। अब भेदभाव अब की परिभाषा किसी भी हित कारक के खिलाफ चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो केवल धर्म चाहती लिग जन्म स्थान विकलांगता या इसमें से किसी भी आधार पर किया गया, अनुचित क्या पक्षपात पूर्ण व्यवहार या कोईं भी कार्यं भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 पर विवाद काफी गहरा गया है उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। जबकि सरकार इसे सामान्य बढ़ाने की पहला बता रही है, विरोधियों का कहना है कि यह असमानता को बढ़ावा देगा समान समाज ने इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिह ने यूजीसी को लिखे अपने पत्र में निमन बातें लिखी है -पिछला वर्ग और दलित वर्ग के छात्रों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होना चाहिए लेकिन नए नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए नया नियम सामान्य समाज के छात्रों के उत्पीड़न का कारण बन सकता है। इस नए अधिनियम का विरोध करने के लिए सवर्ण समाज पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है वही डसना धाम के महंत महा मंडलेश्वर यदि नरसिहानंद गिरि ने गंगा किनारे इस अधिनियम के विरोध के लिए धरने पर बैठने जा रहे थे पर पुलिस ने शांति व्यवस्था के गड़बड़ होने की आशंका से महामंडलेश्वर को वहां जाने से रोक दिया, परिणाम स्वरूप महामंडलेश्वर की समर्थकों ने इसका घोर विरोध किया, कहां जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस अधिनियम और महामंडलेश्वर की हुए व्यवहार के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है पर यह स्पष्ट नहीं है कि उस मजिस्ट्रेट कर त्यागपत्र वुछ और कारणों से है या यूजीसी के नए नियमावली के विरोध में है। यूजीसी का कहना है कि नए नियम साल 2012 के उसे भेदभाव निरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए जारी किए गए हैं उनका तर्व है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 2019 की तुलना में 2023 में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है हकीकत यह भी है कि यह निर्णय हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या और सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्देश के बाद आया है।

वोट की जंग में बजट का दांव! बंगाल से तमिलनाडु तक, 5 चुनावी राज्य को क्या मिला?

(जीएनएस)।

देश का आम बजट 2026 ऐसे वक्त पेश हुआ है, जब सियासी पारा अपने चरम पर है। अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक इसी बीच मोदी सरकार ने संसद में अपना बजट रख दिया। सवाल साफ है - क्या यह सिर्फ आर्थिक दस्तावेज है या चुनावी रणनीति का मजबूत हथियार?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को युवाओं, महिलाओं और विकास की रफ्तार से जोड़कर पेश किया, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार का बजट चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश भी है। आइए एक-एक कर समझते हैं कि बजट 2026 में इन पांच चुनावी राज्यों को क्या-क्या मिला और इसके पीछे की सियासी तस्वीर क्या कहती है।

पश्चिम बंगाल को क्या मिला?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नजर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के मजबूत किले पर है। यही वजह है कि बजट में बंगाल को लेकर खास घोषणाएं देखने को मिलीं।

वित्त मंत्री ने दानकुनि (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया। इस कॉरिडोर से बंगाल और गुजरात के बीच माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी, जिससे उद्योग और व्यापार को सीधा फायदा मिलेगा।

इसके अलावा सिलीगुड़ी को वाराणसी से जोड़ने वाली हाई-स्पीड रेल लाइन की घोषणा भी की गई। उत्तर भारत से पूर्वोत्तर और उत्तर बंगाल को जोड़ने वाली यह रेल लाइन आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे सकती है।

ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दुगार्पुर को एक बड़े हब के तौर पर विकसित करने की योजना भी सामने आई है। हालांकि, इन सबके बावजूद ममता बनर्जी ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि "बंगाल को कुछ नहीं मिला।" ऐसे में बजट को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग और तेज हो गई है।

केरल को इस बजट में इको-टूरिज्म, हेल्थ और एग्रीकल्चर के जरिए साधने की कोशिश की गई है। रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर में केरल को शामिल किया गया है, जिससे राज्य के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। तटीय इलाकों में कछुओं के संरक्षण के लिए 'टर्टल ट्रेल्स' और पुलिकट झील के आसपास

बर्ड-वॉचिंग ट्रेल्स बनाने की योजना भी सामने आई है।

सबसे बड़ा दांव हेल्थ सेक्टर पर खेला गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से पांच रीजनल मेडिकल हब बनाने की घोषणा की गई है, जिनमें मेडिकल टूरिज्म, डायग्नोस्टिक और आयुष सेंटर शामिल होंगे। इससे डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। चूंकि केरल की बड़ी आबादी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है, इसलिए इसे राज्य के लिए बड़ा प्लस माना जा रहा है।

तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, लेकिन बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बजट 2026 में तमिलनाडु को कई ऐसे सेक्टरों में शामिल किया गया, जो भविष्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा में विशेष मिनरल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई। इसे देश की रणनीतिक जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है।

पुलिकट झील के आसपास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करने और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी बजट में शामिल है। इसके साथ ही नारियल, काजू और कोको जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने की घोषणा ने तमिलनाडु के किसानों को राहत देने का संकेत दिया है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह तमिलनाडु के ग्रामीण और तटीय इलाकों को साधने की कोशिश मानी जा रही है।

असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है और बजट में इसका साफ संकेत दिखता है। वित्त मंत्री ने तेजपुर में ठक्टलअठर 2 स्थापित करने का ऐलान किया है, जो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए बड़ा केंद्र बनेगा। यह न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए अहम परियोजना मानी जा रही है।

इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ते हुए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना भी प्रस्तावित की गई है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच मिलेगा।

पांच चुनावी राज्यों में शामिल पुडुचेरी के लिए बजट में कोई बड़ा अलग ऐलान नहीं किया गया। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र का फोकस बाकी राज्यों पर ज्यादा रहा।

कुल मिलाकर बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं दिखता। इसमें विकास की बातें भी हैं और चुनावी गणित भी। बंगाल में कनेक्टिविटी, असम में हेल्थ और पूर्वोत्तर फोकस, तमिलनाडु-केरल में मिनरल्स, टूरिज्म और एग्रीकल्चर - हर राज्य के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की गई हैं।

अब असली सवाल यही है कि क्या बजट की ये घोषणाएं वोट में बदल पाएंगी या जनता इसे सिर्फ चुनावी स्टंट मानेगी। इसका जवाब तो चुनाव नतीजे ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि बजट 2026 ने चुनावी राज्यों की राजनीति को और गर्म कर दिया है।

किसानों के लिए एक ऐसी योजना फसल की खेती करने वालों की लगी लॉटरी

निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए एक ऐसी योजना पेश की है, जो खेती को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मोटी कमाई वाला बिजनेस बना देगी। इस बार सरकार ने केवल नकद मदद देने के बजाय उन फसलों पर फोकस किया है, जिनकी देश और विदेश के बाजारों में बहुत ज्यादा मांग है।

इस बजट का मकसद किसानों को सीधे ग्लोबल मार्केट (अंतरराष्ट्रीय बाजार) से जोड़ना है। चाहे वह नारियल की खेती हो या चंदन और काजू का व्यापार, सरकार ने हर उस रास्ते को चुना है जहाँ से किसान की जेब में ज्यादा पैसा आ सके। तकनीक और नई किस्म के बीजों के साथ, अब खेती करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है।

नारियल किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी

भारत में करोड़ों लोग नारियल की खेती से जुड़े हैं। बजट 2026 में इनके लिए एक खास 'कायाकल्प' योजना शुरू की गई है।

पुराने पेड़ों की छुट्टी: कई बागों में पेड़ बहुत पुराने हो चुके हैं और फल कम देते हैं। सरकार अब इन पुराने पेड़ों को हटाकर नई और अच्छी किस्म के पौधे लगाने में मदद करेगी।

किसे होगा फायदा: इस योजना से देश के करीब 1 करोड़ नारियल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कमाई का मौका: जब पेड़ ज्यादा फल देंगे, तो किसानों की आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी।

काजू और कोको, अब दुनिया में बिकेगा भारत का 'ब्रांड'

सरकार चाहती है कि भारतीय काजू की पहचान पूरी दुनिया में हो। इसके लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है।

प्रीमियम ब्रांड: सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारतीय काजू दुनिया का सबसे मशहूर और महंगा ब्रांड बन जाए।

कोको (चॉकलेट वाली फसल): चॉकलेट बनाने में कोको का इस्तेमाल

होता है। सरकार कोको की खेती और उसके एक्सपोर्ट (निर्यात) को बढ़ावा देगी ताकि किसानों को व्यापारियों से बेहतर रेट मिल सकें।

चंदन की खेती, अब कानूनी और आसान होगी मोटी कमाई

चंदन को सबसे कीमती पेड़ों में गिना जाता है। बजट में इसके लिए भी रास्ते साफ किए गए हैं।

सरकार चंदन उगाने और उसे काटने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी।

अब किसान बिना डरे अपने खेतों में चंदन लगा सकेंगे और उसकी लकड़ी को सही दाम पर बेच सकेंगे। यह लंबे समय में लाखों की कमाई देने वाली फसल साबित होगी।

पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए खास तोहफा

बजट में उन इलाकों का भी ध्यान रखा गया है जहाँ की मिट्टी और मौसम अलग है।

पहाड़ों में सूखे मेवों की बहार

पहाड़ी राज्यों में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स (चिलगोजा) की खेती के लिए खास मदद दी जाएगी। ये चीजें बहुत महंगी बिकती हैं, जिससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

उत्तर-पूर्व में 'अगरवुड'

उत्तर-पूर्व के राज्यों में 'अगरवुड' के पेड़ लगाए जाएंगे।

महंगा तेल और लकड़ी: इसकी लकड़ी और तेल की खाड़ी देशों (दुबई, सऊदी अरब आदि) में बहुत मांग है।

इससे वहां के किसानों को कमाई का एक बिल्कुल नया और बड़ा जरिया मिलेगा।

कार्लोस ने रचा इतिहास, जोकोविच को हरा तोड़ा 16 साल पुराना रिकॉर्ड

(जीएनएस)।

टेनिस की दुनिया को आज एक नया हीरो मिल गया है। स्पेन के 22 वर्षीय सनसनी कार्लोस अल्काराज ने मेलबर्न पार्क में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 (अ४२३१'ल्ल डस्रील्ल 2026) के फाइनल में महान नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही अल्काराज पुरुष टेनिस इतिहास में 'करियर ग्रैंड स्लैम' (सभी चारों मेजर खिताब जीतना) पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।

रॉड लेवर एरेना में खेले गए इस मुकाबले की शुरूआत 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच के पक्ष में रही। जोकोविच ने अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में अल्काराज की सर्विस दो बार तोड़ी और इसे 6-2 से जीतकर अपने 25वें ग्रैंड स्लैम की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि, वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने दूसरे सेट से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने जोकोविच की सर्विस पर दबाव बनाया और दूसरा सेट 6-2 से जीतकर मुकाबले में बराबरी की। तीसरे सेट में दोनों के

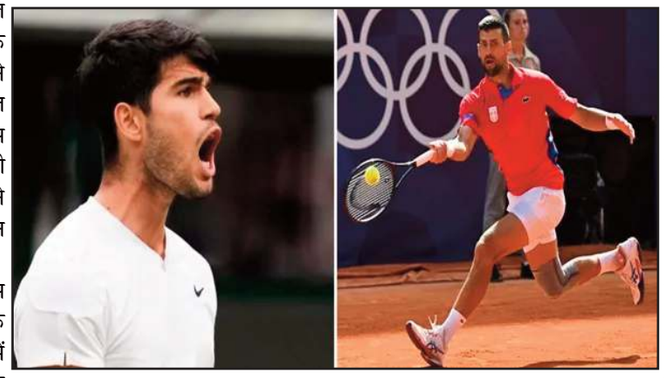

बीच लंबी रैलियां देखने को मिलीं, जिसमें अल्काराज ने 6-3 से बाजी मारकर जोकोविच की पकड़ कमजोर कर दी।

चौथे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने टेनिस के सबसे ऊंचे स्तर का खेल दिखाया। जोकोविच ने मैच को पांचवें सेट तक खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन युवा अल्काराज के पास उनकी हर चाल का जवाब था। अल्काराज ने चौथा सेट 7-5 से जीतकर जोकोविच के अपराजेय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले जोकोविच मेलबर्न में कभी फाइनल नहीं हारे थे।

हार के बाद भी जोकोविच ने जीता दिल

ट्रॉफी समारोह के दौरान जोकोविच ने अल्काराज की ओर इशारा करते हुए कहा कि कार्लोस, तुम जो कर रहे हो वह ऐतिहासिक और महान है। तुम्हारे करियर में अभी बहुत समय बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले 10 सालों में मैं तुम्हें कई बार और देखूंगा।" जोकोविच के इस मजाक पर पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा।

राफेल नडाल को लेकर हुए भावुक

इस दौरान स्टैंड्स में बैठे स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल को देखकर जोकोविच खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मुझे स्टैंड्स में बैठे महान राफा से भी बात करनी है। जाहिर है, आपको वहां देखना और यहां कोर्ट पर न देखना थोड़ा अजीब है। आपके साथ कोर्ट साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।

जब डगमगाई टीम इंडिया की नैया, संकटमोचक बने वेदांत त्रिवेदी! पाकिस्तान के खिलाफ किया कमाल

(जीएनएस)।

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले में आज भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर सिक्स के इस करो या मरो वाले मैच में भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन ऐसे समय में युवा बल्लेबाज वेदांत त्रिवेदी ने दमदार खेल दिखाते हुए टीम इंडिया की पारी को संभाला।

चार गेंदों के भीतर गिरे तीन विकेट - टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत अच्छी रही थी। लेकिन मैच में एक समय ऐसा आया जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए महज 4 गेंदों के भीतर भारत के 3 अहम विकेट चटका दिए। इस अचानक हुए कोलेप्स ने

भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी।

वेदांत त्रिवेदी ने खेली कमाल की पारी- जब स्कोर बोर्ड पर रन कम और विकेटों का दबाव अधिक था। तब वेदांत त्रिवेदी क्रीज पर उतरे। उन्होंने एक छोर को सुरक्षित रखते हुए पाकिस्तान के आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया। वेदांत ने परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढाला और जोखिम भरे शॉट्स के बजाय सिंगल-डबल पर फोकस किया। यह इस टूर्नामेंट में वेदांत त्रिवेदी का पहला अर्धशतक है।

भारतः एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अम्ब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन।

भारत ने 46 रन से न्यूजीलैंड को हराया, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह बने जीत के हीरो

भारत ने 46 रन से न्यूजीलैंड को हराया, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह बने जीत के हीरो

पाकिस्तानः हम्जा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, अली रजा।

शाहरुख खान का कैमियो रजनीकांत की जेलर 2 में हुआ पक्का

(जीएनएस)।

रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'जेलर 2' को उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक माना जा रहा है। पहले भाग की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों की उम्मीदें इसके सीक्वल से काफी बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में कई बड़े सितारे कैमियो करते नजर आएंगे, जिनमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है।

शाहरुख खान की मौजूदगी पर लगी मुहर

शाहरुख खान के 'जेलर 2' का हिस्सा बनने की पुष्टि पहले ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कर चुके थे, लेकिन उस वक्त उनके किरदार को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। अब इस पर से पर्दा उठ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान फिल्म में रजनीकांत के बेहद करीबी और भरोसेमंद दोस्त की भूमिका निभाएंगे।

छोटा लेकिन खास कैमियो रोल

बताया जा रहा है कि शाहरुख का

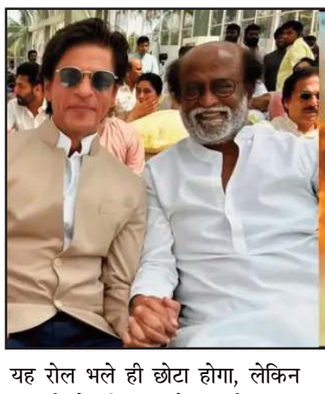

यह रोल भले ही छोटा होगा, लेकिन कहानी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वह फिल्म में कुछ ही मिनटों के लिए नजर आएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगी। शाहरुख ने यह कैमियो रजनीकांत के प्रति सम्मान और दोस्ती के चलते स्वीकार किया है।

अन्य सितारों के कैमियो की भी चर्चा

'जेलर 2' में सिर्फ शाहरुख ही नहीं, बल्कि कई और दिग्गज सितारों के कैमियो की भी खबरें हैं। अभिनेता विजय सेतुपति ने एक इंटरव्यू में शाहरुख की भागीदारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने खुशी-खुशी इस रोल के लिए हामी भरी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल, शिवराजकुमार और विद्या बालन के भी कैमियो करने की अटकलें हैं। फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भाग को भी निर्देशित किया था।

'किंग' में व्यस्त हैं शाहरुख खान

इस बीच शाहरुख खान अपनी अगली मेगा बजट फिल्म 'किंग' की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है और इसके जरिए उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी। फिल्म में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

350 करोड़ बजट की मेगा फिल्म

करीब ₹350 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बन रही 'किंग' शाहरुख खान के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। ऐसे में 'जेलर 2' में उनका कैमियो और 'किंग' की रिलीज-दोनों ही

सीप्लेन निर्माण से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा, आपकी जेब पर कैसा होगा असर?

(जीएनएस)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पर्यटन उद्योग के लिए बड़े ऐलान किए हैं। देश में सीप्लेन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की गई है। इससे टूरिज्म फ्लाइट्स सस्ती होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार की नई नीति के तहत सीप्लेन निर्माण, मेंटेनेंस और ऑपरेशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया जाएगा। इससे निजी कंपनियां इस सेक्टर में तेजी से निवेश करने में दिलचस्पी ले सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तटीय और नदी किनारे बसे पर्यटन स्थलों को नई उड़ान मिलेगी। सीप्लेन ऐसी एयरक्राफ्ट सेवा है जो पानी और जमीन दोनों जगह लैंड कर सकती है। भारत में लंबी तटरेखा, बड़ी नदियां और कई द्वीप हैं। गुजरात, अंडमान-

निकोबार, केरल, गोवा, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में पहले से ही सीप्लेन रूट की संभावनाओं पर काम चल रहा है।

अब निर्माण को बढ़ावा मिलने से टिकट की कीमतों में कमी आएगी और आम पर्यटक भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस 'वॉटर एयरोड्रोम' नेटवर्क विकसित करने पर है। छोटे शहरों और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए वऊअठ जैसी योजनाओं के साथ सीप्लेन को जोड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण होने से आयात पर निर्भरता घटेगी और ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा।

पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सीप्लेन सेवा शुरू होने से उन इलाकों में भी सैलानी पहुंच सकेंगे, जहां सड़क या पारंपरिक एयरपोर्ट बनाना मुश्किल है। इससे होटल, होम-स्टे, वाटर स्पोर्ट्स और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। खासकर द्वीपों और बैकवाटर क्षेत्रों में यह गेमचेंजर साबित हो सकता है।

एविएशन मंत्रालय के मुताबिक शुरूआती चरण में प्रमुख धार्मिक और ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि योजना तय समय पर आगे बढ़ी तो अगले दो-तीन साल में भारत सीप्लेन टूरिज्म का बड़ा हब बन सकता है। सस्ती उड़ानें, कम समय और अनोखा अनुभव यही इस पहल की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

यूपीः लखनऊ सहित अवध के कई जिलों में अच्छी धूप, पर इन इलाकों में आज से बारिश की चेतावनी; कोहरे को लेकर अलर्ट

लखनऊ , (जीएनएस)। यूपी के मौसम में आज से बदलाव आने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में आज से बारिश हो सकती है। मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह ठंड के साथ तेज हवा की वजह से सिहरन महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। सोमवार को इसका असर प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को सुबह बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और आजमगढ़ में घना कोहरा रहा और यहां दृश्यता शून्य दर्ज की गई। इसके अलावा मेरठ में दृश्यता 10 मीटर, बरेली और बलिया में 20, हमीरपुर में 40 और लखनऊ में 50 मीटर रही। प्रदेश में सबसे ठंडा हरदोई रहा जहां पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री, मेरठ में 6.8 डिग्री, कानपुर और बाराबंकी में 7 और राजधानी लखनऊ में 8.8 डिग्री दर्ज किया गया।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक फरवरी से लेकर तीन फरवरी तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस दौरान वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने से कोहरे में कमी आने की संभावना है। चार फरवरी से तापमान में एक बार फिर से गिरावट के आसार हैं। एक फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। दो फरवरी से प्रदेश के अन्य इलाकों में भी आंशिक बारिश हो सकती है।

यहां घना कोहरा रहने की संभावना

देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाके।

यहां आज शीत दिवस के आसार

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके।

धूप पर पछुआ भारी, छूटी कंपकंपी

राजधानी में ठंड शनिवार को फिर लौट आई। सुबह कोहरे और सर्द हवाओं ने स्वागत किया। घरों से निकलने वालों की कंपकंपी छूट गई। करीब नौ बजे तक दृश्यता 100 मीटर से कम रही। तेज रफ्तार से चली पछुआ के आगे धूप बेअसर रही। शाम को भी गलन ने परेशान किया।

कोहरे के कारण सुबह वाहनों की लाइटें जलानी पड़ीं। दिन का तापमान 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का पारा 3.1 डिग्री की गिरावट के साथ 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को भी सुबह कोहरा छाने के आसार हैं। बादलों की लुकाछिपी से दिन में धूप-छांव का खेल चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय नए विक्षोभ के असर से दो फरवरी को राजधानी में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रात के तापमान में चार डिग्री तक की बढ़त के संकेत हैं।

इस बार गर्म रहेगी फरवरी, बारिश भी होगी कम

वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस बार फरवरी पिछले वर्ष के मुकाबले गर्म रहेगी। दिन के मुकाबले रातें ज्यादा गर्म रहेंगी। इसकी वजह ला-नीना का कमजोर और न्यूट्रल होना बताया जा रहा है। गर्माहट की वजह फरवरी में यूपी में एक से ज्यादा विक्षोभ का सक्रिय होना भी है। पूर्वानुमान है कि इस बार फरवरी में बारिश भी सामान्य से कम होगी। रविवार को नया विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से तापमान में फिर

लखनऊ में 3 फरवरी को होगा फार्मा कॉन्क्लेव, यूपी में देश-विदेश की टॉप कंपनियों का होगा जमावड़ा

राजधानी लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य को देश का प्रमुख फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार 3 फरवरी को लखनऊ स्थित ताज होटल में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 : इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश का आयोजन कर रही है। यह कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (ऋउ्अ) और इन्वेस्ट यूपी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

ऋउ्अ के सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वरऊ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मजबूत आधार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने, नीतिगत सुधार लागू

करने और निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार करने पर काम कर रही है।

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में क्या खास?

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में भारत और दुनिया की अग्रणी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हिस्सा लेंगी। प्रमुख प्रतिभागियों में रामको ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी, सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी, मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के चेयरमैन डॉ. सतीश रेड्डी, जायडस लाइफसाइंसेज के चेयरमैन पंकज आर. पटेल और टोरेंट फार्मा के वाइस चेयरमैन गिनाल मेहता शामिल हैं। इसके अलावा, एमएसएन लैबोरेटरीज के एमएसएन रेड्डी, डाबर के निदेशक आदित्य वर्मन और अल्केम के निदेशक संदीप सिंह की उपस्थिति भी कॉन्क्लेव सत्रों में उल्लेखनीय रहेगी।

डॉ. रोशन जैकब ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। इस नीति के तहत निवेशकों को 15 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और बिजली शुल्क से पूर्ण छूट जैसे आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 450 से अधिक फार्मा कॉलेज और एनआईपीईआर रायबरेली, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद हैं, जो कुशल मानव संसाधन का मजबूत आधार उपलब्ध करा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदन से लेकर परियोजना संचालन तक की प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। निवेशकों को त्वरित अनुमोदन और नियामक सहयोग प्रदान करने में ऋउ्अ की भूमिका भी अहम रही है। इसके साथ ही, राज्य के पास रेडी-टू-मूव औद्योगिक भूमि का बड़ा भंडार है, जो उत्तर प्रदेश की निवेश आकर्षण क्षमता को और मजबूत करता है।

बजट में बिहार को मिला सबसे बड़ा तोहफा, इन 4 घोषणाओं से बदलेगी राज्य की किस्मत

(जीएनएस)।

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के विकास को एक नई गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में बिहार को बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से जलमार्ग और हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी के मामले में "बड़ी सौगात" मिली है।

सरकार का मुख्य ध्यान राज्य को एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है, जिससे न केवल माल ढुलाई की लागत कम होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह बजट बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पटना में बनेगा शिप रिपेयर इकोसिस्टम

बजट में पटना और वाराणसी में एक समर्पित शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य इनलैंड वॉटरवेज (अंतर्देशीय जलमार्ग) को मजबूत करना है। अब गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स को मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना होगा। स्थानीय स्तर पर मेंटेनेंस की सुविधा मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए नए

रोजगार सृजित होंगे।

जलमार्गों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता विकल्प बनाने पर जोर दिया है। पटना और वाराणसी के विकास के साथ-साथ गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के किनारे जलमार्ग नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय युवाओं के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वे इस बढ़ते जलमार्ग क्षेत्र में अपनी जगह बना सकें। यह पहल बिहार को पूर्वी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, बजट 2026 में प्रस्तावित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर पटना समेत बिहार के कई प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों को सीधा फायदा होगा और राज्य में निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी।

महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की पहल

बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देते हुए बजट में बिहार के हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। यह कदम कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे महिलाओं की शिक्षा और श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ेगी। आधुनिक रेल और जल परिवहन के साथ यह सामाजिक पहल बिहार को एक आधुनिक और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में अहम है।

शिवपुरी में इक्विटी रेगुलेशंस विरोध में भारत बंद उग्र, भाजपा बजट कार्यक्रम पर प्रदर्शनकारियों का हमला-मंच तोड़ा,

(जीएनएस)।

शिवपुरी जिले में रविवार को यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में बुलाया गया भारत बंद हिंसक रूप धारण कर गया। जहां अधिकांश जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, वहीं करेरा और शिवपुरी शहर में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के बजट प्रसारण कार्यक्रमों को निशाना बनाया।

प्रदर्शनकारियों ने मंच पर चढ़कर नारेबाजी की, एलसीडी स्क्रीन बंद कराई, कुर्सियां फेंकी और तोड़फोड़ की। इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और भाजपा का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत को सुरक्षा कारणों से वहां से भागना पड़ा।

करेरा में क्या हुआ?

करेरा कस्बे में पुलिस सहायता केंद्र के पास भाजपा ने केंद्रीय बजट 2026 के प्रसारण और चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू होने के कुछ देर बाद ही यूजीसी नियमों के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए।

प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए सीधे मंच पर धावा बोल दिया। उन्होंने एलसीडी स्क्रीन बंद करा दी, कुर्सियां उखाड़कर फेंकी और मंच पर तोड़फोड़ की। माहौल इतना उग्र हो गया कि सुरक्षा कर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा। रणवीर सिंह रावत को तत्काल वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

कार्यक्रम पूरी तरह रद्द कर दिया गया।

शिवपुरी जिला मुख्यालय पर भी हमला

शिवपुरी शहर में भी भाजपा का बजट प्रसारण कार्यक्रम चल रहा था। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय के पास पहुंचकर मंच पर चढ़कर नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां और अन्य सामान फेंककर व्यवधान पैदा किया। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप

प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 बहुजन छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से उनका विरोध और तेज हो गया है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार इन नियमों को लागू नहीं कर रही और जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है।

कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ उग्र तत्वों ने हिंसा भड़काई। हालांकि, भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सुनियोजित हमला था और प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक कार्यक्रम को निशाना बनाकर लोकतंत्र पर हमला किया।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

शिवपुरी पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल कुछ लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

भाजपाः प्रदेश प्रवक्ता ने इसे "लोकतंत्र पर हमला" करार दिया और कहा कि विपक्षी ताकतें विकास के एजेंडे को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही हैं।

कांग्रेस और अन्य विपक्षः यूजीसी नियमों पर बहस को लोकतांत्रिक बताया और हिंसा की निंदा की, लेकिन सरकार पर आरोप लगाया कि वह छात्रों की भावनाओं को समझ नहीं रही।

प्रदर्शनकारी संगठनः भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और ओबीसी संगठनों ने हिंसा से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था।

यह घटना शिवपुरी जिले में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रही है। यूजीसी नियमों पर विवाद अब सड़कों से लेकर अदालत और राजनीतिक मंचों तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन होने की आशंका जताई जा रही है।

36 साल की ऐश्वर्या राजेश ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया फोटोग्राफर ने भाई के सामने कर डाली ऐसी हरकत

(जीएनएस)।

फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की चचाएं नई नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर सामने आने वाले अनुभव इस कड़वी सच्चाई को फिर उजागर कर देते हैं। अब साउथ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने अपने शुरूआती दिनों का एक ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है।

ऐश्वर्या राजेश का शॉकिंग खुलासा

ऐश्वर्या राजेश ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया है कि करियर की शुरूआत में उन्हें एक फोटोग्राफर की ओर से बेहद आपत्तिजनक मांग का सामना करना पड़ा था। उनके इस बयान ने लोगों को हैरान कर दिया है।

पॉडकास्ट में शेयर किया दर्दनाक अनुभव

ऐश्वर्या राजेश हाल ही में डिजिटल क्रिएटर निखिल विजयेंद्र सिम्हा के पॉडकास्ट में नजर आई थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। इस इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई, जिसमें अभिनेत्री ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया है।

'भाई को बाहर बैठाया, मुझे अंदर ले गया'

-ऐश्वर्या राजेश ने बताया कि उस समय वह बहुत कम उम्र की थीं और इंडस्ट्री में नई-नई आई थीं। एक फोटोशूट के लिए वह अपने भाई के साथ गई थीं लेकिन फोटोग्राफर ने

उनके भाई को बाहर बैठने के लिए कहा और उन्हें अंदर ले गया।

-ऐश्वर्या राजेश के अनुसार अंदर जाकर फोटोग्राफर ने उन्हें इनरवियर थमाते हुए कहा कि वह उनकी बॉडी देखना चाहता है। ये सुनकर वह अंदर तक हिल गई थीं। ऐश्वर्या राजेश ने बताया कि उस उम्र में उन्हें इंडस्ट्री की ज्यादा समझ नहीं थी और कुछ पल के लिए वह स्थिति को समझ नहीं पाई थीं लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने फोटोग्राफर से कहा कि उन्हें अपने भाई से पूछकर आना होगा।

निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलानः टियर 2-3 शहरों में हर साल 1000 करोड़, आम आदमी को मिलेगा तकनीकी का फायदा

(जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 'बजट 2026' पेश किया, जो देश में आर्थिक प्रगति को नई गति देने और प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर केंद्रित रहा। बजट के बाद प्रेस कार्न्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्ति त मंत्री ने बजट के संदर्भ में आज अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुधारों और नीतियों पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा बजट का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सुधार प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे।

वित्त मंत्री का ऐलान- 2-3 टियर शहरों में हर साल 1000 करोड़

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दे रही है और हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह तकनीक द्वारा संचालित है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि तकनीक का लाभ आम आदमी तक पहुंचे।

'देश की अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है लक्ष्य'

वित्त मंत्री ने सीतारमण ने कहा, बजट में समग्र आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को अगले कुछ वर्षों में 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, बुनियादी ढाँचे के विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है।

महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि

सामाजिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है। 'पीएम गरीब कल्याण योजना' के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 'जल जीवन मिशन' के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों को और गति मिलेगी।

कौन थी पी. विजया, 2 मासूम बच्चों संग ट्रेन के आगे क्यों लगाई छलांग? वजह

(जीएनएस)।

हैदराबाद में 1 फरवरी 2026 की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास 38 साल की पी. विजया ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना रात करीब 12:40 बजे की है, जब सनतनगर जा रही मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया।

यह सिर्फ एक ट्रेन हादसा नहीं, बल्कि संभावित सामूहिक जान देने का मामला है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं - कौन थीं विजया, क्या हुआ, और मौत की वजह क्या हो सकती है...

18 साल की बेटी चेतना रेड्डी और 17 साल की बेटे विशाल रेड्डी - के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना रात करीब 12:40 बजे की है, जब सनतनगर जा रही मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया।

यह सिर्फ एक ट्रेन हादसा नहीं, बल्कि संभावित सामूहिक आत्महत्या का मामला है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं - कौन थीं विजया, क्या हुआ, और मौत की वजह क्या हो सकती है।

38 साल की पी. विजया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद के हाई-टेक सिटी के पास एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थीं। पति सुरेंद्र रेड्डी दुबई में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही तुरंत हैदराबाद लौट आए। बेटी चेतना रेड्डी (18 साल, इंटरमीडिएट/क्लास 12 की छात्रा), बेटा विशाल रेड्डी (17 साल, क्लास 11 का छात्र) के साथ विजया ने जान दी। घटना हैदराबाद के बोडुप्पल इलाके में हरिथावनम कॉलोनी या हरिताहारम कॉलोनी , चेंगिचरला क्षेत्र के पास हुई। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था। विजया अच्छी कमाई करती थीं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते

थे। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि आर्थिक तंगी कोई वजह नहीं लगती।

घटना कैसे हुई? क्या-क्या हुआ रात में?

समयः 31 जनवरी 2026 की आधी रात, करीब 12:40 बजे।

स्थानः चेरलापल्ली और घटकेसर रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक (MMTS लाइन, किलोमीटर मार्कर 207/2 के पास)।

कैसे पहुंचींः विजया अपनी कार से चेरलापल्ली स्टेशन पहुंचीं, कार पार्क की और फिर बच्चों के साथ ट्रैक पर चली गईं।

ट्रेनः सनतनगर जा रही मालगाड़ी। लोको पायलट सुशैन महतो ने तीनों को ट्रैक पर देखा, लेकिन वे नहीं हटे। गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया।

अलर्टः लोको पायलट ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। चेरलापल्ली के डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट टी. ज्योति ने शिकायत दर्ज की।

पुलिस एक्शनः सिकंदराबाद जीआरपी इंस्पेक्टर बी. साईश्वर गौड़ की टीम मौके पर पहुंची। मौत की पुष्टि की। शवों को गांधी अस्पताल ले जाया गया पोस्टमॉर्टम के लिए।

केसः बीएनएसएस की धारा 194 (संदिग्ध मृत्यु) के तहत मामला दर्ज। जांच जारी।

मौत की वजह?

पुलिस को विजया की खड़ी कार से एक नोट मिला। उसमें लिखा है-

'मैं इस जीवन को पसंद नहीं करती। बहुत कोशिशों के बावजूद मुझे यह जीवन अच्छा नहीं लगता।'

'मैं बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें भी साथ ले जा रही हूं।'

'इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरी मौत और बच्चों की मौत के लिए कोई और दोषी नहीं।'

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का संकेत मिलता है। कोई टिकट नहीं मिला, मतलब जानबूझकर ट्रैक पर गए। सटीक वजह अभी जांच में है।

संत रविदास अपने भक्तों का कल्याण करें- योगी आदित्यनाथ

:लखनऊ में सीएम बोले- हमें विभाजनकारी को सिर नहीं उठाने देना, एकजुट रहो

लखनऊ (जीएनएस)।

लखनऊ के संत रविदास मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा- संत रविदास अपने भक्तों और मानने वालों का कल्याण करें। संतों ने इस देश के लिए काम किया। संतों से यही संदेश मिला कि हमें विभाजनकारी ताकतों को सिर नहीं उठाने देना है। संत रविदास ने भी एकजुट रहने का संदेश दिया।

1 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर देशभर में संत रविदास की 649वीं जयंती मनाई गई। लखनऊ के बाराबिरवा में कानपुर रोड स्थित संत रविदास मठ में सीएम योगी ने संत रविदास को वर्तमान समय का भी बड़ा लीडर बताया। सीएम ने कहा कि संत रविदास को जब लोगों ने कहा कि चलिए गंगा स्नान करने, तो उन्होंने अपने काम को महत्व दिया। कहा- मन चंगा तो कठौती में गंगा।

जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था। आप याद करिए, जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने मध्य काल में 12 शिष्य बना। सभी शिष्य अलग-अलग जातियों से थे। एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया। उन्होंने यह सब समाज को जोड़ने के लिए किया था।

संत रविदास बनारस में रहते थे। वह निर्गुण भक्ति शाखा के संतों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं।

समाज को जोड़ने का कार्य संतों ने किया

समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य संतों ने किया, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। 600 साल पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी रविदास महाराज जी प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी प्रेरणा थी कि ऐसा राज्य होना चाहिए, जहां सबको अन्न मिले। हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जिने के अवसर मिल सके।

उन्होंने 600 साल पहले ये उपदेश दिए। एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। हो सकता है कि मुगलों और ब्रिटिश सरकार ने भुला दिया हो, आजादी के बाद की सरकारों ने भुला दिया हो। लेकिन, जब भाजपा सरकार बनी तो हर गरीब का अकाउंट खुलवाया। हर घर में शौचालय बनवाया। रसोईघर के

कनेक्शन दिए। पिछले 6 वर्ष से हर जरूरतमंद पर राशन दिया जा रहा है। यह सद्गुरु रविदास जी ही प्रेरणा है।

सीएम योगी के साथ मठ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे।

सीएम योगी के साथ मठ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे।

2017 से पहले संत की जन्मभूमि तक जाने का रास्ता नहीं था

2017 से पहले संत रविदास की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन में जाने का मार्ग नहीं था। लंगर का हॉल नहीं था। आज फोरलेन की सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा गया है। वहां संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। आज एक धाम बन गया है।

हम सबके मन में महापुरुषों के प्रति यही आदर का होना चाहिए। विभाजनकारी ताकतें बाटेंगी। हमें गुलामी के कालखंड को याद करते हुए उन्हें सिर उठाने का अवसर नहीं देता है। एकजुट होकर समाज की संरचना को मजबूत करना होगा। यही सद्गुरु रविदास जी महाराज जी प्रेरणा थी।

सनातन से जुड़े पुनरुद्धार के लिए सरकार काम कर रही है। बिना भेदभाव के काम किए जाए हैं। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। एक करोड़ भक्त स्नान कर चुके हैं।

सीएम योगी भाजपा नेताओं के साथ रविदास मठ में पहुंचे हुए थे। पहले उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

सीएम योगी भाजपा नेताओं के साथ रविदास मठ में पहुंचे हुए थे। पहले उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

रविदासजी की तुमड़ी मां गंगा ने ले ली

संत रविदास से जुड़ी एक कहानी सुनाई। एक बार संत रविदास जी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम है। मेरी ओर से मां गंगा को तुमड़ी दे देना। दूसरे संतों ने स्नान और पूजा अर्चना की, लेकिन कुछ नहीं किया।

फिर उन्हें याद आया कि रविदास जी ने भी कुछ दिया है, तो उन्होंने तुमड़ी निकालकर चढ़ाई तो मां गंगा ने हाथ फैलाकर तुमड़ी ले ली। यह देखकर संत चकित हो गए। इस तरह से संत रविदास ने कर्म को प्रधानता दी। उन्होंने कहा- मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठिन साधना से तपा हुआ शरीर संकट के समय में चुनौती का सामना करता है।

लखनऊ के संत रविदास मठ में संत रविदास की यह प्रतिमा स्थापित है।

संत रविदास मठ में आयोजित हुआ जयंती समारोह

माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुबह 10:30 बजे संत रविदास मठ परिसर में जयंती समारोह की शुरूआत हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी ने समानता, प्रेम और सामाजिक न्याय का जो संदेश दिया, वह आज के समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का जीवन और दर्शन सामाजिक समरसता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है और उनके विचारों को अपनाकर ही समतामूलक समाज का निर्माण संभव है।

वाराणसी के क्षीर गोवर्धन स्थित संत रविदास की जन्मस्थली पर लंगर चल रहे हैं।

सामाजिक समरसता और भाईचारे पर दिया गया जोर

कार्यक्रम के दौरान संत रविदास जी के उपदेशों और रचनाओं का स्मरण किया गया। वक्ताओं ने उनके द्वारा जाति भेद, ऊंच-नीच और सामाजिक असमानता के खिलाफ दिए गए संदेशों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया।

जयंती समारोह में दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने संत रविदास जी को नमन किया। भजन-कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के समापन पर संत रविदास जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया गया।

रोहित शेट्टी के घर पर लॉरेंस ने करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर दी चेतावनी

(जीएनएस)।

मुंबई के पॉश जुहू इलाके में स्थित मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास 'शेट्टी टावर्स' के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात के बाद न सिर्फ इलाके में दहशत फैल गई, बल्कि अब यह भी सामने आया है कि रोहित शेट्टी और अभिनेता सलमान खान के घरों पर हुए हमलों के पीछे एक ही गैंग का हाथ बताया जा रहा है।

चार राउंड फायरिंग, घर के अंदर थे रोहित शेट्टी

मिली जानकारी के मुताबिक, बीती रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग के वक्त रोहित शेट्टी घर के अंदर मौजूद थे, हालांकि इस घटना में उन्हें या उनके परिवार को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेर लिया गया। फिलहाल शेट्टी टावर्स के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है।

सलमान खान केस से जुड़ रहा है कनेक्शन

जांच में सामने आया है कि इस

हमले की जिम्मेदारी उसी गैंग ने ली है, जिसने इससे पहले अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। उस मामले में भी बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई थीं। तब मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आया था और उस वारदात को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा गया था।

सोशल मीडिया पोस्ट से जिम्मेदारी का दावा

अब रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर हरमन संधू ने यह पोस्ट साझा की है। पोस्ट में दावा किया गया है कि पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन बात नहीं मानी गई, इसलिए यह "ट्रेलर" दिखाया गया।

खुली धमकी से बढ़ी चिंता

पोस्ट में आगे बेहद गंभीर और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भविष्य में और बड़े हमलों की चेतावनी देते हुए पूरे बॉलीवुड को भी निशाना बनाया गया है। गैंग ने अपने संदेश में यह भी कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो हालात और खराब हो सकते हैं।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, जांच तेज

इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच अलर्ट मोड पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच की जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर से मुंबई में हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान ने लिया टी 20 वर्ल्ड कप पर फाइनल फैसला, भारत के खिलाफ मैच से हुआ बाहर, अब आईसीसी का क्या होगा एक्शन?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान सरकार ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपना आधिकारिक और अंतिम फैसला सुना दिया है। रविवार, 1 फरवरी 2026 को सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन वह भारत के खिलाफ होने वाले अपने सबसे बड़े मुकाबले का बहिष्कार करेगी। यह निर्णय क्रिकेट जगत में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है।

पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसने राष्ट्रीय टीम को वर्ल्ड कप में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि, बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित ग्रुप-स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। सरकार का यह रुख आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के विरोध में एक कूटनीतिक 'विरोध प्रदर्शन' के रूप में देखा जा रहा है।

बहिष्कार की असल वजह

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाकर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। दरअसल, बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच किसी तटस्थ स्थान (जैसे श्रीलंका) पर शिफ्ट करने की मांग की थी। आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसका पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान का तर्क है कि जब भारत के मैच श्रीलंका में हो सकते हैं, तो बांग्लादेश के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया।

इस फैसले के बड़े परिणाम

पाकिस्तान के इस कदम से टूर्नामेंट का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। क्रिकेट के नियमों के अनुसार, मैदान पर न उतरने की स्थिति में भारत को 'वॉकओवर' मिल जाएगा और बिना मैच खेले ही उसे अंक दे दिए जाएंगे। व्यापारिक दृष्टि से, भारत-पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया होता है। इस एक मैच के रद्द होने से ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापनदाताओं को करोड़ों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है, जिसकी भरपाई के लिए आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर भारी जुमार्ना भी लगा सकती है।

दिवंगत नेता अजित पवार को निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी सौगात, ड्रीम प्रोजेक्ट पुणे को मिला हाई स्पीड कॉरिडोर

(जीएनएस)।

एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार का सबसे बड़ा सपना पुणे को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करना था। वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि पुणे को आधुनिक परिवहन, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और तेज कनेक्टिविटी की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है।

दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार पुणे शहर के विकास और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। निकाय चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार-बार दोहराया था कि पुणे को आने वाले सालों में मेगा कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलेंगे।

पुणे को मिला हाई स्पीड कॉरिडोर

- पुणे-मुंबई और पुणे-हैदराबाद के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को महाराष्ट्र के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।

- इस परियोजना से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि उद्योग,

आईटी, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

- अजित पवार हमेशा कहते थे कि पुणे की असली ताकत उसकी कनेक्टिविटी में है। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए तो यह शहर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का मजबूत विकल्प बन सकता है।

क्या सोचा था, क्या हो गया!

बजट में ये 5 बड़े ऐलान सुनना चाहती थी जनता, पर हाथ खाली

कनेक्टिविटी होगी बेहतर

विशेषज्ञों का मानना है कि हाई स्पीड रेल परियोजना से पुणे में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। नए औद्योगिक हब विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। अजित पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पुणे मेट्रो, रिंग रोड और आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की पैरवी की थी। उनका मानना था कि तेज और सुरक्षित परिवहन ही किसी शहर को वर्ल्ड क्लास बनाता है।

निर्मला सीतारमण की घोषणा अजित पवार के विजन पूरा होने की दिशा में एक अहम कदम है। पुणे के नागरिकों में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि इससे शहर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार, यह कॉरिडोर सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला कदम है। आने वाले वर्षों में पुणे को स्मार्ट और ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में यह सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

बजट 2026 पर रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, दिल्ली वालों को क्या मिलेगा फायदा?

(जीएनएस)।

केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देशभर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान खासा चर्चा में है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के त्रिनगर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट भाषण को सुना और इसे विकास आधारित सोच का मजबूत दस्तावेज बताया। उनका कहना है कि यह बजट न सिर्फ आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को भी और मजबूत करेगा।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपने की साफ झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि आज पेश किया गया बजट समाज के हर वर्ग को छूता है और कारोबार, रोजगार व विकास के नए रास्ते खोलता है।

कैपेक्स पर जोर से राज्यों को क्या मिलेगा फायदा?

रेखा गुप्ता ने खास तौर पर पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दिए गए जोर की सराहना की। उन्होंने कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपये के बड़े आवंटन से राज्यों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस तरह का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सेवाओं और राज्य स्तरीय परियोजनाओं को नई रफ्तार देगा। उनका मानना है कि बड़े

स्तर पर पूंजी खर्च से न सिर्फ तात्कालिक विकास होगा, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ आर्थिक ग्रोथ का आधार भी तैयार होगा।

दिल्ली के लिए बजट में क्या अवसर हैं?

दिल्ली के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट शहरी विकास को तेज करने का बड़ा मौका देता है। इससे सिविक सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा और ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश होगा, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में दिल्ली अपने लक्ष्यों को और तेजी से आगे बढ़ा सकेगी।

केंद्र और राज्य की साझेदारी क्यों है अहम? (डील्ल३१ र३३ी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का मजबूत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लिए दिए गए फंड सही परियोजनाओं तक पहुंचें, जिनका असर जमीन पर दिखे। यह समन्वय विकास को ज्यादा प्रभावी और लोगों के लिए उपयोगी बनाएगा।

युवाओं और रोजगार पर बजट का फोकस कितना अहम?

रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर दिए गए जोर को भी सराहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के अवसर देना और उन्हें देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाना इस बजट की बड़ी ताकत है। इसके साथ ही सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और उसे पर्यटन से जोड़ने की सोच को भी उन्होंने सराहनीय बताया।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को कैसे मिलेगा बल?

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बढ़ा हुआ बजट आवंटन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती देगा। इससे राज्यों को अपने नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। आधुनिक शहरों का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार दिल्ली जैसी महानगरों की प्राथमिकताओं से मेल खाता है।

विकास के साथ वित्तीय अनुशासन क्यों जरूरी?

रेखा गुप्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि निवेश के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संतुलित बजट प्लानिंग से राज्य अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकेंगे।

कुल मिलाकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री के मुताबिक बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक ठोस और व्यावहारिक कदम है, जिसमें केंद्र और राज्यों की साझेदारी देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

नेपाल से बांग्लादेश तक, बजट में मोदी सरकार ने लुटाए करोड़ों! देखें किस देश को कितने रुपए की मदद

(जीएनएस)।

: बजट 2026-27 में भारत सरकार ने अपनी "पड़ोसी पहले" नीति को और मजबूत करते हुए अपने पड़ोसी और रणनीतिक मित्र देशों के लिए सहायता राशि का महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, यह सहायता भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने और दक्षिण एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भूटान को सबसे अधिक सहायता मिलना जारी है, जबकि अन्य देशों के लिए भी उनकी जरूरतों और रणनीतिक महत्व के आधार पर बजट आवंटित किया गया है।

भूटान और नेपाल: सबसे बड़े लाभार्थी

भूटान को इस वर्ष सबसे अधिक ₹2,288.55 करोड़ की सहायता दी गई है, जो दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक और जलविद्युत संबंधों को दशार्ती है। वहीं, नेपाल के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है (जिसमें से ₹100 करोड़ विशेष श्रेणी में हैं)। यह राशि नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा।

मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका: हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारत ने मालदीव और मॉरीशस दोनों के लिए ₹550-550 करोड़ का प्रावधान किया है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करने के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह सहायता मुख्य रूप से बंदरगाह विकास, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इन निवेशों के माध्यम से भारत अपने "सागर" विजन को साकार कर रहा है।

अफगानिस्तान और म्यांमार: मानवीय और विकास सहायता

चुनौतियों के बावजूद, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए ₹150 करोड़ की सहायता जारी रखी है, जो वहां चल रहे मानवीय कार्यों और शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन देगी। म्यांमार के लिए ₹300 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कालादान मल्टी-मोडल प्रोजेक्ट और सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं। यह आवंटन स्पष्ट करता है कि भारत राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी अपने पड़ोसी देशों के विकास और मानवीय जरूरतों के प्रति प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश और अन्य मित्र देश: क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार

बांग्लादेश के लिए ₹60 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो मुख्य रूप से कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण परियोजनाओं पर केंद्रित है। इसके अलावा, मंगोलिया (₹25 करोड़) और सेशेल्स (₹19 करोड़) जैसे देशों को दी जाने वाली सहायता भारत के बढ़ते वैश्विक पदचिह्न और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति उसके समर्पण को दशार्ती है। यह छोटा निवेश भी उन देशों के साथ मजबूत राजनयिक और सुरक्षा संबंध बनाने में दूरगामी परिणाम देता है।

3 और 4 फरवरी की रात रेलवे चलाएगा दो एक्सट्रा स्पेशल लोकल ट्रेन, जानिए वजह

(जीएनएस)।

पश्चिम रेलवे ने शब-ए-बारात के पर्व पर यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, 3 और 4 फरवरी, 2026 की दरमियानी रात को दो विशेष धीमी लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये अतिरिक्त सेवाएं मुंबई के चर्चगेट और विरार स्टेशनों के बीच संचालित की जाएंगी।

इन विशेष सेवाओं में पहली चर्चगेट-विरार लोकल (स्पेशल-1) है। यह ट्रेन 4 फरवरी को तड़के 2:35 बजे चर्चगेट से रवाना होगी। अपने निर्धारित मार्ग पर सभी स्टेशनों पर रुकते हुए, यह सुबह 4:15 बजे विरार स्टेशन पहुंचेगी।

इसी तरह, दूसरी ट्रेन विरार-

चर्चगेट लोकल (स्पेशल-2) 4 फरवरी की सुबह 1:42 बजे विरार से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह विशेष लोकल भी पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर रुकेगी और सुबह 3:22 बजे चर्चगेट पहुंचेगी।

लोकल ट्रेनें रूट के सभी स्टेशनों पर रुकेंगी

पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ये दोनों विशेष लोकल ट्रेनें अपने मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। इन अतिरिक्त सेवाओं का मुख्य उद्देश्य शब-ए-बारात के दौरान यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करना और उन्हें आरामदेह एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।